पेज थ्री देहरादून

हमारा दून

देहरादून बृहस्पतिवार 9 अप्रैल 2020 पेज 8

मैडम रजनी रावत सीएम को मुख्यमंत्री राहत कोष में 11 लाख रूपये का चेक देते हुए।

संक्षिप्त समाचार

मैडम रजनी रावत ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 11 लाख

संवाददाता देहरादून। कोविड–19 के दृष्टिगत मैडम रजनी रावत ने मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु 11 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपा। जिला उपाध्यक्ष, जिला पंचायत देहरादून श्री वीर सिंह चौहान ने 25 हजार रूपए मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु दिए हैं। डायरेक्टर परियोजना यूजेवीएनएल श्री सुरेश चंद्र बलूनी तथा डायरेक्टर फाइनेंस यूजेवीएनएल श्री सुधाकर बडोनी ने 51–51 हजार रूपए के चेक मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु दिए हैं। डॉ तृप्ति बहुगुणा स्वास्थ्य निदेशक, स्वास्थ्य निदेशालय देहरादून ने 51 हजार रूपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु दिया है। एसोसिएशन ऑफ फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर्स सिडकुल, रानीपुर, हरिद्वार ने भी 7 लाख 51 हजार रूपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु दिया है।

मेयर से की प्राइवेट वर्कर्स को भी मदद दिलाने की मांग

संवाददाता देहरादून। भाजपा नेत्री व नगर निगम की पूर्व उपाध्यक्ष डा. बबीता सहोत्रा ने दून शहर के महापौर सुनील उनियाल गामा से उनके आवास पर भेंट कर घरों में काम करने वाली महिलाओं व कुछ ऐसे लोग जो होटल व दुकानों में प्राइवेट कार्य कर अपना जीवन यापन कर रहे थे व जिनके राशन कार्ड भी नहीं बने हुए हैं कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकलॉक डाउन के कारण वह अपने कामकाज नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण उनका रोजी रोटी का संकट बना हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने मेयर सुनील उनियाल गामा को इस बात से अवगत करवाया।

कोरोना संक्रमण से सम्बंधित राहत कार्यों को लेकर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

संवाददाता देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की निवर्तमान प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कोरोना वायरस संक्रमण में बचाव के लिए चल रहे राहत कार्यों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य कोरोना महामारी की चपेट में है। जिसके चलते पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस अवसर पर गरिमा ने कहा कि पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री यदा–कदा जनता के बीच पहुंचकर सरकारी रसोइयों का मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से सामाजिक संगठनों के द्वारा चलाई जा रही रसोइयों पर निर्भर दिखाई पड़ती है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि गरीब, दिहाड़ी–मजदूरों या अन्य जरूरतमन्दों के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से अभी तक पके भोजन के वितरण की समुचित व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही है।

कैबिनेट के फैसले

- राज्य खाद्य योजना के 10 लाख से ज्यादा राशनकार्ड धारकों को तीन महीने अप्रैल, मई और जून में दोगुना राशन मिलेगा।
- उत्तराखंड चिकित्सा सेवा विभाग में लैब टेकनिशियन के पदों की सेवा नियमावली को मंजूरी, 347 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ।
- कैबिनेट बैठक में कोरोना को लेकर हुई चर्चा। राज्य में कोरोना टेस्ट की जांच लायी जा रही है तेजी 823 पॉजिटिव मरीजों के लिए राज्य के पास हैं बेड। राज्य में 251 वेंटिलेटर राज्य के पास है, 455 राज्य के पास आईसीयू है, 31 हजार 77 राज्य में एन–95 मास्क उपलब्ध है। राज्य में कोरोना के लिए अवश्यकता अनुसार पर्याप्त इंतजाम।
- राज्य में खाद्य सामग्री का प्रशासन के जरिए होगा वितरण।
- राज्य सरकार ने केंद्र को लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश, निर्णय केंद्र पर छोड़ा।
- राज्य में चार तरह के राशन कार्ड पर सरकार का फैसला।
- राज्य में मंत्री और विधायकों के 30 प्रतिशत वेतन की कटौती। 2 साल तक विधायक निधि में 1– 1 करोड़ की सालाना कटौती। अगले दो सालों तक होगी कटौती मंत्री विधायक प्रभारी मंत्री घर से ही करेंगे विकास समीक्षा।

उत्तराखंड में लॉकडाउन जारी रखने के पक्ष में सरकार

कैबिनेट की बैठक

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में लॉकडाउन की मौजूदा व्यवस्था आगे भी जारी रखने और इस संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। साथ ही केंद्र सरकार की भांति प्रदेश सरकार भी कोरोना संकट के मद्देनजर राज्य में दो साल के लिए विधायक निधि स्थगित रखने के साथ ही मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और दायित्वधारियों के वेतन में 30 फीसद कटौती करने का निर्णय लिया है।

त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड के विधायकों की निधि से दो साल के लिए महज एक–एक करोड़ की कटौती का ही फैसला लिया गया। विधायकों के वेतन में एक साल के लिए 30 फीसदी कटौती की गई है।

उत्तराखंड कैबिनेट फैसलाः नहीं कटेगा दायित्वधारियों का वेतन

अलबत्ता दायित्वधारियों के वेतन–भत्तों में कोई कटौती नहीं होगी। त्रिवेंद्र कैबिनेट पूरी तरह से केंद्र की मोदी कैबिनेट की तरह तमाम फैसले नहीं ले सकी।

दो घंटे तक चली कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसलों के बारे शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट की तर्ज पर ही त्रिवेंद्र कैबिनेट ने भी विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के वेतन में एक साल के लिए 30 फीसदी कटौती का फैसला किया है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि भत्तों आदि के बारे में भी केंद्र की गाइड लाइन के अनुसार ही फैसला होगा। उन्होंने

लॉकडाउन पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को किया अधिकृत

पूरी तरह केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर नहीं किया गया अमल

साफ कर दिया गया कि सरकारी दायित्ववालें नेताओं के वेतन में कटौती पर कोई फैसला नहीं हुआ।

केंद्र ने जहां सांसदों की निधि दो साल के लिए पूरी तरह से स्थगित की है। वहीं उत्तराखंड में विधायकों की निधि में से केवल एक–एक करोड़ की कटौती दो साल के लिए होगी। यहां बता दें कि एक विधायक को उसकी निधि में सालाना साढ़े तीन करोड़ रुपये मिलते हैं।

शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि करोना संकट से निपटने के लिए सरकार ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि लाकडाउन अवधि में कमी आदि पर कोई भी फैसला लेने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ही अधिकृत कर दिया है।

उत्तराखंड में भी कई प्रतियोगिता स्थगित

लॉकडाउन

■ यूट्यूब और वीडियो कॉल बनी मददगार

देहरादून। **संवाददाता**

कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए देश–विदेश में लॉकडाउन हैं। जिस कारण सभी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इसमें खेल प्रतियोगिता भी शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक को एक साल के लिए आगे खिसका दिया गया है। आइपीएल के आयोजन पर अभी भी संशय बरकरार है। आइपीएल पर जल्द फैसला किया जाएगा। उत्तराखंड में भी कई प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई हैं। मार्च में शुरू होने वाला नारायण गुरुंग (जिक्स) मेमोरियल फुटबाल टूर्नामेंट अब मई में होगा। अप्रैल में होने वाला जीसी नागलिया मेमोरियल आल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट अब सितंबर में होगा। आल इंडिया उत्तराखंड गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट पर भी संशय बरकरार है।

प्रतियोगिताएं स्थगित होने से खेल और खिलाड़ियों को भी नुकसान हो रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। जिससे खिलाड़ी स्वयं और अन्य लोग सुरक्षित रहें। इसका पालन करते हुए आयोजकों ने यह कदम उठाए हैं। लॉकडाउन के दौरान क्रिकेटरों को उनके कोच वीडियो कॉल की मदद से खेल सुधारने के लिए टिप्स दे रहे हैं। वहीं कुछ खिलाड़ी यूट्यूब की मदद से सीनियर खिलाड़ियों के वीडियो देखकर अपनी तकनीकी सुधार रहे हैं।

घर में अभ्यास कर रहे खिलाड़ी

देश में चल रहे लॉकडाउन के बावजूद खिलाड़ी अभ्यास जारी रखे हुए हैं। खिलाड़ी घरों में रहकर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्रिकेटर तो घरों के आंगन व छत पर स्टंप लगाकर स्वजनों के सहयोग से खेले की कमियों को दूर करने में लगे हैं। ऐसे वीडियो कुछ खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया में भी साझा किए हैं। इन वीडियो से अन्य युवा खिलाड़ी भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। उत्तराखंड सीनियर टीम के तेज गेंदबाज दीपक धपोला वीडियो में बल्लेबाजी का अभ्यास करते नजर आए। ऐसे ही एक अन्य वीडियो में रणजी खिलाड़ी करनवीर कौशल भी घर में स्वजनों की मदद से बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं। वहीं भारतीय जूनियर टीम के खिलाड़ी आर्यन जुयाल भी अपने घर पर रहकर ही एक्सरसाइज व खेल की तैयारी कर रहें हैं।

लॉक किए गए क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी, पीएसी भी तैनात

संवाददाता डोईवाला। डोईवाला की केशवपुरी बस्ती और झबरावाला में रविवार को कोराना संक्रमित मिलने पर प्रशासन ने दोनों क्षेत्रों को लॉक कर दिया था। वहीं, अब इन क्षेत्रों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इसके साथ साथ ही वहां पर पीएसी तैनात कर दी गई है।

सुरक्षा की दृष्टि से केशवपुरी बस्ती, गैस गोदाम मार्ग, झबरावाला मुख्य मार्ग, बुल्लावाला राजकीय इंटर कॉलेज सहित गांव के अन्य संपर्क मार्गों में बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही में प्रतिबंध लगा है। मंगलवार को भी उप जिलाधिकारी लक्ष्मी राज चौहान, प्रभारी तहसीलदार अपूर्वा पांडेय, नायब तहसीलदार रूप सिंह, प्रभारी खंड विकास अधिकारी भगवान सिंह नेगी, सीओ राकेश देवली, कोतवाल प्रदीप बिष्ट ने सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही पुलिस को दिशा–निर्देश दिए।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिंटर्स,74/9,आराघर,देहरादून
से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०–
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून
ही मान्य होगा।